बदलकर जिले की हदतक कर दिया गया है, उस जिले में रहने वाले को ही दिया जाए। यह निर्णय लिया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन जिन्होंने पहले से ही दूसरे जिलों में ले रखा है, उनके बारे में क्या होगा ?

श्री पी० शिव शंकर : जिनको दे दिया गया है, उसमें तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बेनामी तरीके से चला रहा हो और यह इत्तला आप देंगे तो हम ऐक्शन लेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जिले के आदमी को ही लोकल मान लिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि जहां पर दूसरे जिले वालों को लेटर आफ इन्टेन्ट दिया गया है वहाँ पुनः जिले के लोगों को ही मौका दिया जाए ? जैसे मिर्जापुर में गाजियाबाद का कोई व्यक्ति चला गया है तो उसको देखते हुए पुनः वहां के स्थानीय लोगों को ही मौका देने का कष्ट करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : पिछली गाइड लाइन के तहत अगर एक जिले के आदमी को दूसरे जिले के लिए लेटर आफ इन्टेन्ट मिला है तो उसमें कुछ करना मुश्किल है लेकिन अगर लेटर आफ इन्टेन्ट लेकर बेनामी तरीके से बैठा हुआ है, खुद काम नहीं करता है तो उस मामले में हम ऐक्शन ले सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : दूसरी जगह के लोगों को किसकी पैरवी पर दिए गए हैं ?

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Question No. 607 - Shri Krishna Chandra Pandey.

(*Interruptions*)

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir, let him say. (*Interruptions*). Sir, these gentlemen are making all types of allegations. Have I ever spoken to Mr. Shiv Shankar on the allotment of gas agencies ? Ask the minister. If the minister confirms their charge, I go, but if the Minister does not have and now these friends must accept or go.

(*Interruptions*)

PROF. K.K. TEWARY : Sir, a member of Parliament, Shri Bahuguna, has admonished the minister. Can he deny it ?

(*Interruptions*)

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir The allegation is totally illfounded. I make an open challange that if the Minister confirms that I have spoken to him, written to him or pressurised him or obstructed him in any manner with regard to allotment of Gas agency I am willing to go. Otherwise, these people, who are absolutely making irresponsible allegations must go.

(*Interruption*)

PROF, MADHU DANDAVATE : He will go in 1985, Sir.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri Krishna Chandra Pandey.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Question No. 607.

(*Interruptions*)

Application of M/s Pfizer on Protinex

*607. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the details of application of M/s Pfizer on Protinex;

(b) whether Protinex is a drug or a food item;

(c) when was it made food item, when a drug and what is its status today;

(d) was any approval given for Protinex under DPCO in 1970 and 1979; and

(e) if so, the details of the approval ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE) : (a) There was no application for Protinex as such. The application was

for Protein Hydrolysate. Details are as below :

Date of Application	Date of Licence	Capacity approved
22.4.1954	16.12.1954	18 tonnes/annum
24.5.1960	28.9.1960 to	36 tonnes/annum(SE)
29.6.1962	15.4.1963 to	110 tonnes/annum(SE)

(b) and (c) Except between 1972 and 1976 Pfizer have been marketing Protinex as a drug item.

(d) No approval has been given.

(e) Does not arise.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रोटिनेक्स 1972 से 1976 तक किन-किन कारणों से ड्रग के रूप में बाजार में नहीं बेचा गया और इसे किस रूप में बेचा गया ?

क्या यह सच नहीं है कि फाइजर कम्पनी विदेशी है ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार भी इसमें शेयरहोल्डर है ? क्या यह सच नहीं है कि लाभ का पूरा पैसा फाइजर कंपनी विदेश ले जाती है और इससे भारत की अपार क्षति हो रही है ?

श्री वसन्त साठे : जैसा मैंने जवाब में कहा है कि लाइसेन्स प्रोटीन हाईड्रोलीसेट को मिला था 1954 । में उस वक्त डी० पी० सी० ओ० (ड्रग प्राइस कन्ट्रोल आर्डर) नहीं था । बाद में जब डी० पी० सी० ओ० लागू हुआ तो उन्होंने यह दलील दी कि : प्रोटिनेक्स ड्रग नहीं है, यह तो न्यूट्रिएन्ट है । इस दरम्यान दूसरे भी काफी इस तरह के कम्प्लान, बाल-आमूल, प्रोमीलान, प्रोटीन्यूल दीगर-दीगर न्यूट्रिएन्ट अलग-अलग कम्पनियों के बाजार में आये । प्रोटिनेक्स ड्रग नहीं है, यह कहकर वह बेचने लगे ।

1976 में जब लगा कि वह न्यूट्रिएन्ट नाम से बाजार में बिकता नहीं है तो उन्होंने फिर एप्लाई किया कि डी० पी० सी० ओ० में इसे ले आया जाये । उस पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया हैं क्योंकि हम बुनियादी बात यह देखना चाहते हैं कि क्या यह फूड आइटम में आयेगा ? न्यूट्रिएन्ट ड्रग आइटम में नहीं आता है, तो फिर प्राइस कन्ट्रोल का सवाल पैदा नहीं होता । आता है तो लाया जायेगा । यह आज की भूमिका है ।

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या यह विदेशी कम्पनी है, तो यह विदेशी कम्पनी है, और क्या चाहते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे : क्या इसमें भारत सरकार शेयरहोल्डर है और इसका पूरा लाभांश विदेश को जा रहा है, भारत की अपार क्षति हो रही है, इसका जबाब नहीं आया ।

श्री वसन्त साठे : जितनी विदेशी कम्पनी है, वह लाभांश तो बाहर ही ले जाती हैं । इसलिए यह निर्णय लिया गया ड्रग पालिसी में, कि इनकी इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा, वह बात अब चल रही है ।

श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में प्रोटिनेक्स का कितना उत्पादन हुआ और उसकी कितनी क्षमता का लाइसेंस दिया गया ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोटिनेक्स कभी दवा के रूप में और कभी फूड के रूप में बाजार में बेची जाती है, यह कब तय होगा कि यह दवा है या फुड है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया 1963 में उनको 110 टन का लाइसेंस मिला और 1954 में 18 टन का था । यह मैंने खुद ही बताया है कि यह फूड है या ड्रग है—इसके ऊपर जल्दी ही निर्णय लेंगें ।

PROF. N.G. RANGA : How many years will you take?

SHRI VASANT SATHE : They have taken all these years. I will take only a few months.

Creation of Separate Telegraph Engineering Division for Mizoram

*608. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the creation of a separate Telegraph Engineering Division for Mizoram has been proposed and subsequently approved by Government on a sub-standard basis as a special case;

(b) if so, the date with effect from which the proposal has been approved; and

(c) if not, the likely date by which it would be approved and the reasons for delay?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (VIJAY N.PATIL) : (a) No Sir, the creation of a separate Telegraph Engineering Division for Mizoram has not been proposed. The proposal is for placing a higher level officer for the better management of Telecom. assets in the Union Territory of Mizoram which has been taken up for approval.

(b) The proposal which is under consideration has so far not been approved.

(c) No definite date can be given at this stage.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : May I know from the hon. Minister whether this proposed higher level office would meet the demands of the area and, if so, what is the exact designation of the officer and what will be his function?

SHRI VIJAY N. PATIL : The proposed higher level officer will definitely meet the demands of the area. The higher level officer is proposed for this area considering its strategic importance and other factors relating to this Union Territory.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : What is the exact designation of this higher level officer?

SHRI VIJAY N. PATIL : His designation will be Director, Telecom.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Is the Department considering any other proposal to have similar arrangement in other parts of the country?

SHRI VIJAY N. PATIL : This area, that is, Mizoram, as I have already mentioned, is of strategic importance and it is a Union Territory. Consindering the separate entity of the area, we are proposing the higher level officer there. We are proposing such officers not only in Mizoram but in Imphal, Agartala, Kohima, Itanagar and Aizwal, that is, north-eastern region. Such proposals are not under our consideration for other areas although they may be hilly areas.

SHRI K. PRADHANI : Q. No. 610.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K.L. BHAGAT) : With your permission, Sir, I am changing the expression "harijans" used in the Answer to "Scheduled castes and Scheduled Tribes". I am sorry for the lapse.

Films on Tribals in Orissa

* 610. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Governmet of India have given encouragement to making of films on Tribals; and

(b) if so, the names of such films particularly in the State of Orissa on the lives and living conditions of the Tribes ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIMENTARY AFFAIRS

(SHRI H. K. L. BHAGAT) : (a) Films Division publicises the policies and programmes of the Government for the benefit of the people in general, and for rural, tribal and weaker sections in particular. It